

सफलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन मेहनत करने वालों को जरूर मिलती है।
- अज्ञात



परिवर्तन का मकसद

परीक्षा के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन और देशों में भी किया जाता है लेकिन उनका जोर विद्यार्थियों की प्रतिभा को उभारने पर होता है। अभी जबकि सीबीएसई ने परीक्षा पद्धति को सुधारने का फैसला किया है तो ऐसा करते हुए उसको सारे पहलुओं पर ध्यान देना होगा।

रुचि जड़ौत

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्नपत्रों के प्रारूप में बुनियादी बदलाव लाने का फैसला किया है। इस परिवर्तन का मकसद शिक्षा-परीक्षा को मशीनी धज से बाहर निकालकर उनमें तर्क क्षमता और कल्पनाशीलता के लिए गुंजाइश बढ़ाना है। एसोचौम द्वारा आयोजित शिक्षा शिखर सम्मेलन में सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि बदलाव की इस प्रक्रिया के तहत अगले साल होने वाले बोर्ड एग्जाम में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 20 फीसदी ऑब्जेक्टिव सवाल हल करने होंगे, जबकि 10 फीसदी सवाल रचनात्मक सोच-विचार पर आधारित होंगे। 2023 तक दोनों परीक्षाओं के प्रश्नपत्र पूरी तरह रचनात्मक, आलोचनात्मक और विश्लेषण क्षमता की परख करने वाले हो जाएंगे। एक अरसे से कहा जा रहा है कि

वर्तमान परीक्षा प्रणाली जड़ होकर महज एक नंबर गेम में बदल गई है। जो जितना बेहतर तरीके से सवालों के जवाब रट लेता है वह उतने ज्यादा अंक पा लेता है। तमाम स्कूलों और कोचिंग संस्थानों का मकसद बच्चों को कुछ नया सिखाना नहीं बल्कि वह कुंजी पकड़ाना भर रह गया है, जिससे अंकों का खजाना खुलता है। यूं कहें कि वे बच्चों को रटू तोता बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की बहुतायत के चलते सारा जोर सूचना पर है और ज्ञान की उपेक्षा हो रही है। एनसीईआरटी ने अपनी एक रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि पैसंड प्रतिशत बच्चों को छपा हुआ टेक्स्ट पढ़ना तो आता है लेकिन उसका अर्थ वे नहीं जानते। इस तरह बच्चों के भीतर न तो रचनात्मकता जगाई जा रही है, न ही उनमें जिज्ञासा या

खोजबीन की ललक पैदा हो रही है। शोध और अन्वेषण में भारत के फिसड्डी रह जाने की मुख्य वजह यही है। झोली भर-भरकर नंबर पाने वाले बच्चे आगे चलकर क्या कर पाते हैं, यह वरिष्ठ भारतीय उद्यमियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शिकायतों से जाहिर होता है। वे साफ कहते हैं कि भारत में इंजीनियरों के पास सिर्फ डिग्री होती है, योग्यता नहीं।

परीक्षा के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन और देशों में भी किया जाता है लेकिन उनका जोर विद्यार्थियों की प्रतिभा को उभारने पर होता है। अभी जबकि सीबीएसई ने परीक्षा पद्धति को सुधारने का फैसला किया है तो ऐसा करते हुए उसको सारे पहलुओं

पर ध्यान देना होगा। न सिर्फ प्रश्न तय करने में बल्कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी समर्थ लोगों को शामिल करना होगा, जिनका काम सिर्फ आंसर शीट से मिलान करना न हो।

भारतीय शिक्षा को मशीनी बनाने में शिक्षकों का भी बड़ा योगदान है। उन्हें न तो पर्याप्त प्रशिक्षण मिला होता है, न ही उनके भीतर कोई नई दृष्टि पैदा करने की कोशिश की जाती है। प्रायः वे उसी पद्धति को ढोते रहते हैं, जिससे खुद पढ़कर आए होते हैं। इसलिए परीक्षा में बदलाव से पहले क्लास में शिक्षण के तौर-तरीकों में कल्पनाशीलता और नवाचार को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए कुछ अलग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ सकता है। सरकार पैसा लगाए तो तीन-चार साल का वक्त इसके लिए कम नहीं है।



आपकी किस्मत

श्रीदेवी माधवन

वृद्धावस्था मनोरोग पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल के अध्ययन के अनुसार, "बागवानी करने या क्रासवर्ड पहेली सुलझाने जैसे शौकों पर ध्यान देने से आप थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफें भूल जाते हैं और इससे आपका मूड भी बदल जाता है। किसी ऐसी चीज में रुचि रखना अच्छा है जहां आपको किसी के माता, पिता, पार्टनर या कर्मचारी की भूमिका निभानी नहीं पड़ती है। वहां केवल आप होते हैं।" जब मैं भी एक ऐसे ही वैकल्पिक रुचिकर कार्य की तलाश कर रहा थी, तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे जेहन में भी थी। जैसा कि सब कहते हैं योजना ए के विफल हो जाने पर जीवन में हमेशा योजना बी होनी चाहिए। यह बात मुझ जैसे शौकीनों के लिए बिलकुल सही है क्योंकि हम किसी एक शौक को एक लंबे समय तक पूरा करते-करते उससे उब जाते हैं और फिर दूसरे शौक या रुचिकर कार्य की तलाश करने लगते हैं।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

नरमी नदारद

बतौर गृहमंत्री अमित शाह सबसे पहले जिस राज्य के दौरे पर गए वह जम्मू-कश्मीर है। लोकसभा में जो पहला बिल उन्होंने पेश किया वह भी जम्मू-कश्मीर से संबंधित रहा। इससे यह जरूर साफ होता है कि गृह मंत्रालय की प्राथमिकता सूची में जम्मू-कश्मीर सबसे ऊपर है। लेकिन इस आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि उनकी अगुआई में सरकार की जम्मू-कश्मीर नीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। शाह की यात्रा से पहले हुर्रियत का बयान आया था कि वह सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। इसके बाद संभावना जताई जाने लगी थी कि गृहमंत्री इस संबंध में आगे कोई घोषणा कर सकते हैं। लेकिन अमित शाह ने न तो अपने कश्मीर दौरे में ऐसा कोई ऐलान किया, न ही लोकसभा के अपने भाषण में ऐसा कुछ कहा जिससे हुर्रियत को उसके हाल पर छोड़ देने के सरकारी रवैये में किसी बदलाव का संकेत मिलता हो।

असल में, कश्मीर पर मोदी सरकार का नजरिया पिछली तमाम सरकारों से कुछ मामलों में बुनियादी तौर पर अलग है। वाजपेयी सरकार समेत अब तक की तमाम सरकारें कश्मीर पर कभी गरम तो कभी नरम रुख अपनाती रही हैं, लेकिन उनका जोर उग्र और हिंसक धाराओं को आम लोगों से अलग-थलग करने पर ही रहता आया है। नतीजा यह कि हिज्बुल मुजाहिदीन से लेकर लश्करे तैयबा तक विभिन्न संगठन अपनी हिंसक रणनीति की अलग-अलग व्याख्याओं के साथ वहां अपनी राजनीतिक उपस्थिति बनाए रखते थे। सरकार की इस सख्त नीति का सटीक संदेश जम्मू-कश्मीर के आम लोगों तक सही ढंग से पहुंचा हो या नहीं, पर घाटी से बाहर देशवासियों के बड़े हिस्से ने इसे न केवल समझा है बल्कि पसंद भी किया है।

एक बार फिर यह साबित हो गया कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा अजेय रही है। दरअसल 2017 की प्रचंड जीत के बाद उत्तराखंड में हुए तमाम चुनावों में भाजपा ने बाजी मारी है।

जारी है सीएम त्रिवेन्द्र का अविजित सफर

अतुल जोशी

पिथौरागढ़ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्व. प्रकाश पंत की पत्नी श्रीमती चंद्रा पंत ने कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमती अंजू लुठी को हराकर प्रदेश में भाजपा की जीत का सिलसिला जारी रखा है। खास बात ये है कि चंद्रा पंत ने स्व. प्रकाश पंत से भी बड़ी जीत दर्ज की है। प्रकाश पंत ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी मयूख महर को 2684 मतों से हराया था, जबकि चंद्रा पंत की जीत का मार्जिन 3267 है। यही नहीं 2017 में प्रकाश पंत को 50.23 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि चंद्रा पंत को उपचुनाव में 51.6 प्रतिशत मत मिले हैं।

पिथौरागढ़ उपचुनाव में जीत के बाद एक बार फिर यह साबित हो गया कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा अजेय रही है। दरअसल 2017 की प्रचंड जीत के बाद उत्तराखंड में हुए तमाम चुनावों में भाजपा ने बाजी मारी है। पिछले तीन साल में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में ही उपचुनाव, नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव लड़े, लिहाजा इन चुनावों में सीएम त्रिवेन्द्र की साख दांव पर थी।

भाजपा को एक हार मिलती तो मुख्यमंत्री



त्रिवेन्द्र के विरोधी उनके खिलाफ और मुखर हो जाते। लेकिन सीएम त्रिवेन्द्र ने सूझबूझ और धैर्य से सभी बाधाओं को पार कर पार्टी को जीत दिलाई। साल 2018 में थराली उपचुनाव में सीएम त्रिवेन्द्र ने खुद मोर्चा संभाला और श्रीमती मुन्नी देवी शाह को जीत दिलवाई। इसके बाद 2018 के नगर निकाय चुनाव भी सीएम की छवि पर लड़े गए। भाजपा ने सात में से पांच मेयर पदों पर

प्रचंड जीत हासिल की, तो सीएम त्रिवेन्द्र की छवि और मजबूत होती गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर नरेंद्र-त्रिवेन्द्र की जुगलबंदी और रणनीति पर जनता ने भरपूर प्यार लुटाया और पांचों सीटें रिकॉर्ड मतों से भाजपा की झोली में डाली। सीएम त्रिवेन्द्र की रणनीति के आगे विरोधी पस्त हुए, साथ ही बार बार सत्ता परिवर्तन के कयासों पर भी विराम लग गया। लोकसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव भाजपा के लिए लिटमस टेस्ट से कम नहीं था। त्रिवेन्द्र सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए दो बच्चों और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की शर्त रख दी थी इसके बावजूद भी जनता ने त्रिवेन्द्र सरकार के कामकाज को कसौटी पर रखकर भाजपा के पक्ष में जनमत दिया।

12 में 9 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 पर जीत मिली। भाजपा कुल 89 पदों में से 45 पर अपनी पार्टी के ब्लॉक प्रमुख बनाने में कामयाब रही। कई जगहों पर भाजपा के बागी जीते, लेकिन कांग्रेस महज 26 ब्लॉक प्रमुख पदों पर जीत दर्ज कर सकी। पिथौरागढ़ उपचुनाव के बाद एक बार फिर यह साबित हो गया कि सूबे में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र द्वारा प्रदेश की जनता के हित में लिये गये निर्णयों को जनता ने सराहा है।

सूडूकु बवताल-5177						* * * * *									
7	8		2	6	3	4	3	2	9	5	6	1	7	8	
			4			6	8	5	7	1	4	9	2	3	
1	3	5		8		9	1	7	3	8	2	4	5	6	
			2		1									7	8
6	7				9									2	
2	8	5												6	1

अपना ब्लॉग

आत्महत्या की तैयारी में लगे हैं हम

रमेश जोशी। पिछले दिनों बेहद लोकप्रिय हुई फिल्म सीरीज अवेजर्स का खलनायक थैनोस धरती सहित ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म कर देता है। थैनोस का मानना है कि इस आबादी ने पर्यावरण और संसाधनों को बर्बाद करके ब्रह्मांड के लिए खतरा पैदा कर दिया है, लिहाजा ब्रह्मांड को बचाने के लिए आधी आबादी को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इस सीरीज के सुपर हीरो ब्रह्मांड को थैनोस से बचाने के लिए महायुद्ध लड़ते हैं और आखिर में कामयाब होते हैं। लेकिन हकीकत में जो हो रहा है, वह इसके एकदम उलट है। पहली बार कम से कम इस धरती पर आश्चर्यजनक रूप से हकीकत ने कल्पना को हरा दिया है। यहां किसी थैनोस को हमें नष्ट करने के लिए कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धरती पर रहने वाले हम इंसान पहले ही सामूहिक आत्महत्या के रास्ते पर चल पड़े हैं। बल्कि इससे भी भयानक यह बात है कि हम चार अरब वयस्क तीन अरब बच्चों और निर्दोष युवाओं को भी मौत की तरफ घसीट कर ले जा रहे हैं, जो इस पाप में अभी तक भागीदार नहीं बने थे।

